



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 474 ]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2003/आश्विन 7, 1925

No. 474 ]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2003/ASVINA 7, 1925

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2003

सा.का.नि. 775(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 637क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 26 जुलाई, 2001 में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (कंपनी कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 555(अ) तारीख 26 जुलाई, 2001 को संशोधित करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के पैरा 1 के खंड (च) के उपखंड (i) में मद (आ) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(आ) सावधि और आवर्ती निक्षेपों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विहित ब्याज को उस अधिकतम दर से अधिक ब्याज नहीं देगी जो गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियां अपने लोक निक्षेपों पर संदाय कर सकती हैं;”।

[फा. सं. 5/12/2001-सीएल-V]

राजीव महर्षि, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2003

G.S.R. 775(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 637A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby amends the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Company Affairs), number G.S.R. 555(E), dated the 26th July, 2001 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 26th July, 2001, namely:—

In the said notification, in paragraph 1, in clause (f), in sub-clause (i), for item (B), the following item shall be substituted, namely:—

“(B) offer interest on fixed and recurring deposits not exceeding the maximum rate of interest prescribed by the Reserve Bank of India that the Non Banking Financial Companies can pay on their public deposits;”.

[F.No. 5/12/2001-CL-V]

RAJIV MEHRISHI, Jt. Secy.